



आमंत्रण का गढ़पत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 391]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 12, 1979/अग्रहायण 21, 1901

No. 391] NEW DELHI, WEDNESDAY DECEMBER 12, 1979/AGRAHAYANA 21, 1901

इस भाग में विभिन्न पृष्ठ अलग अलग घोषणाओं के रूप में रखा जा सकता है।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

प्रधिकार

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1979

सं० का० नि० 688(प्र).—गान्धीजी जारी की गई निम्न-
लिखित उद्योगणा संविधानाधारण के सुविधायें प्रकाशित की जा रही हैं:—

यह मुझे, भारत के राष्ट्रपति नीलम भंडारी रेही को अग्रम राज्य
के राज्यपाल से एक नियोग प्राप्त हुई है, और इस विधाई नवा मुझे प्राप्त
राज्य संचालन पर विचार करने के बाद में या समाधान हो गया है कि ऐसी
स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें राज्य का भासन भारत के संविधान
(जिसे इसके पश्चात् “संविधान” कहा गया है) के उपर्योगों के
अनुसार नहीं छलाया जा सकता है;

अब अब मैं, संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
तथा उत्तर नियन्त्रित मुख्य व्यवस्था वाली अस्य सभी शक्तियों का प्रयोग
करने हुए एन्द्रधारा उद्योगणा करना हूँ कि मैं—

(क) उक्त राज्य की सरकार के सभी कार्य और इस राज्य के
राज्यपाल में निहित, तथा उनके द्वारा प्रयोगशक्ति गमी शक्तियों,
भारत के गोपनीय के रूप में स्वयं संभालना हूँ;

(ख) नाप्रित करना हूँ कि उक्त राज्य के विभिन्न मंडल की शक्तियों
संबद्ध द्वारा या उनके प्रांतीय के अन्तर्गत प्रयोगशक्ति होंगी;
और

(ग) विनाशित भानुरेक और पारिणामिक उपर्योग करना हूँ
जो इस उद्योगणा के उद्देश्यों को प्रमाणी बताने के लिये मुझे
प्रयोगशक्ति या वांछनीय प्रवाल होते हैं; पर्याप्ति—

(i) इस उद्योगणा के उपर्योग खंड (क) के आधार पर
में द्वारा संभाले गए कार्यों और शक्तियों का प्रयोग
करने में, मेरे लिये भारत के राष्ट्रपति के रूप में उस
माना तक जिस तक मैं ठीक मनौ उक्त राज्य के
राज्यपाल के माध्यम से कार्य करना विधिवृत्त होगा;

(ii) उक्त राज्य के संबद्ध में विभागों के नियन्त्रित उपबंधों
के प्रयोग को एन्द्रधारा विधिवृत्त किया जाता है,
पर्याप्ति—

अनुच्छेद 3 के परन्तुक का उत्तरा भाग जिसने का
संबद्ध राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विभिन्न संकल को निवेश
करने से है;

अनुच्छेद 151 के खंड (2) का उत्तरा भाग जिसने
का संबद्ध भारत के नियन्त्रक और महानेत्रा परीक्षक
द्वारा राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों
को राज्य के विधानसंसद के समक्ष रखे जाने से है;
अनुच्छेद 163 और 164;

अनुच्छेद 166 के खंड (3) का उत्तरा भाग जिसने
का संबद्ध राज्य भरकार के कार्य के संदर्भों के बीच
बटवारे से है;

अनुच्छेद 167 और 169;

अनुच्छेद 171 का खंड (1) अनुच्छेद 175, 176,
और 177;

अनुच्छेद 179 का खंड (ग) भी; उम्म अनुच्छेद का
प्रथम परन्तुक;

अनुच्छेद 181, 188, 189, 193, 194, 196 और
198;

अनुच्छेद 199 का खंड (3) और खंड (4);

अनुच्छेद 208 से 211 (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं);

अनुच्छेद 213 के खंड (1) का परन्तुक और खंड (3) का परन्तुक; और

अनुच्छेद 323 के खंड (2) का उतना भाग जिनमें
का संबंध शापन महिन रिपोर्ट को राज्य के विधान मंडल
के समझ द्वारे जाने से है;

(iii) संविधान में राज्यपाल के प्रति किसी निवेश का प्रधं
उस राज्य के संबंध में राष्ट्रपति के प्रति निवेश लगाया
जाएगा और उसमें राज्य के अधीन मंडल या विधान
सभा के प्रति किसी निवेश का, जहाँ तक उसका संबंध
उसके हृष्यों और उसकी शक्तियों से है, अर्थ, जब तक
कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, संसद के प्रति
निवेश लगाया जाएगा और विशिष्टतया अनुच्छेद 213
में राज्यपाल और राज्य के विधान मंडल या उसके
मंदनों के प्रति निवेशों का प्रधं, क्रमशः गण्डपति और
मंदव या उसके मंदनों के प्रति निवेश लगाया जाएगा;

परन्तु इसमें कोई बात अनुच्छेद 153, अनुच्छेद
155 से लेकर अनुच्छेद 159 तक (जिसमें या दोनों
सम्मिलित है), अनुच्छेद 299 और अनुच्छेद 361 तथा
द्वितीय अनुसूची के पैरा 1 से लेकर पैरा 4 तक (जिसमें
ये दोनों सम्मिलित हैं) के उपबंधों पर प्रभाव नहीं
डालेगी और उन राष्ट्रपति को उस खंड के उपखंड (i)
के अधीन उस सीमा तक जहाँ तक वह ठीक समझे
उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने से
निवारित करेगी ;

(iv) संविधान में राज्य के विधान मंडल के या एतद्वारा
जनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निवेश
का ऐसे प्रधं लगाया जाएगा मात्रों उसके अन्तर्गत इस
उच्चोषणा के आधार पर संसद द्वारा या राष्ट्रपति
या संविधान के अनुच्छेद 357 के खंड (1) के उपखंड
(क) और असम साधारण खंड अधिनियम, 1915
(1915 का असम अधिनियम 2) जैसा कि वह असम
राज्य में लागू है, में निविष्ट प्रत्यक्ष अधिकारी द्वारा
राज्य के विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग करते
हुए जनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति निवेश
है, और साधारण खंड अधिनियम 1897 (1897 का
10) का उतना भाग जितना राज्य विधियों पर लागू
है, ऐसे किसी अधिनियम या विधि के बारे में ऐसे
प्रभावी होगा मात्रों यह उस राज्य के विधान मंडल का
अधिनियम हो।

[सं. 5/11013/5/79 सी. एस आर.]

नहीं विली,

12 दिसंबर, 1979

नीलम संजीव रेडी

राष्ट्रपति

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 1979

G.S.R. 688(E).—The following Proclamation by the President is published for general information:—

Whereas, I, Neelam Sanjiva Reedy, President of India have received a report from the Governor of the State of Assam and after considering the report and other information received by me, I am satisfied that a situation has arisen in

which the Government of that State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as "the Constitution");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I—

(a) assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State;

(b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and

(c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely:—

(i) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State;

(ii) the operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended, namely:—

so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State;

so much of clause (2) of article 151 as relates to the laying before the Legislature of the State of the reports submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor-General of India;

articles 163 and 164;

so much of clause (3) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State;

articles 167 and 169;

clause (1) of article 174; articles 175, 176 and 177;

clause (c) of article 179 and the first proviso thereto;

articles 181, 188, 189, 193, 194, 196 and 198;

clauses (3) and (4) of article 199;

articles 208 to 211 (both inclusive);

the proviso to clause (1) and the proviso to clause (3) of article 213; and

so much of clause (2) of article 323 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State;

(iii) any reference in the Constitution to the Governor shall, in relation to the said State, be construed as a reference to the President, and any reference therein to the Legislature of the State or the Houses thereof, shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and in particular, references in article 213 to the Governor and the Legislature of the State or the Houses thereof, shall be construed as references to the President and to Parliament or the Houses thereof respectively;

Provided that nothing herein shall affect the provisions of article 153, articles 155 to 159 (both inclusive); article 299 and article 61 and paragraphs 1 to 4 (both inclusive) of the Second Schedule or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State;

(iv) any reference in the Constitution to Acts or laws of or made by the Legislature of the State shall be construed as including a reference to Acts or laws made, in exercise of the powers of the Legislature of the State, by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution and the Assam General Clauses Act 1915 (Assam Act 2 of 1915) as in force in the State of Assam and so much of the

general Clauses Act, 1897 (10 of 1897) as applies
to State laws, shall have effect in relation to any
such Act or law, as if it were in Act of the Legis-
lature of the State.

ORDER

New Delhi, the 12th December, 1979

G.S.R. 689(E).—The following Order by the President is published for general information :—

In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the Proclamation issued on this the 12th day of December, 1979, by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Assam and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution or under any law in force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State.

New Delhi;

The 12th December, 1979.

[No. 5/11013/5/79-CSR]
NEELAM SANJIVA REDDY,
President

मारेश

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1979

सं० ४० लि० ६८९(ए) :—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया गवा निम्नलिखित मारेश सर्वोच्चाधारण के मुक्तनाये प्रकाशित किया जा रहा है :—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मेरे द्वारा भाज दिसम्बर, 1979 के बारहवें दिन जारी की गई उद्घोषणा के अंडे (ग) के उपर्युक्त (1) का मनुस्करण करते हुए मैं एतद्द्वारा निवेश देता हूँ कि भासम राज्य सरकार के सभी कार्य और संविधान के अधीन या उस राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस राज्य के राज्यपाल में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियाँ, जिनको राष्ट्रपति ने उक्त उद्घोषणा के अंडे (क) के आधार पर स्वयं संभाल लिया है, राष्ट्रपति के अधीक्षण, निवेशन और नियंत्रण के अध्याधीन रहते हुए, उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगी।

नई दिल्ली,
12 दिसम्बर, 1979

नीलम संजीव रेडी
राष्ट्रपति

[सं० ५/११०१३/५/७९-सी० एस० भार०]
एम० एल० कम्पानी, अपर सचिव

NEELAM SANJIVA REDDY,
President

[F. No. V/11013/5/79-CSR]

M. L. KAMPANI, Addl. Secy.

